उड़ीसा राज्य

बनाम

नलिनिकान्त मुदुली

12 अगस्त 2004

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए फैसले पर भरोसा करते हुए कार्यवाही रद्द कर दी गई-अपील पर, मामलों को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा गया

व्यावसायिक आचरण - खारिज किए गए फैसले का हवाला देना - एक ऐसे फैसले का हवाला देना जिसे उसी उच्च न्यायालय की बड़ी बेंच या सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इस तथ्य का खुलासा किए बिना कि इसे खारिज कर दिया गया है, गंभीर चिंता का विषय है - बार के सदस्य, जैसा कि न्यायालय के अधिकारियों के रूप में यह परम कर्तव्य है कि वे न्यायालय की सहायता करें न कि उसे गुमराह करें।

प्रतिवादी-अभियुक्त ने धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाएँ दायर कीं। आरोपपत्र रद्द करने के लिए; आईपीसी के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने और गैर-जमानती वारंट को वापस लेने की प्रार्थना को खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक और इस आधार पर दायर की गई थी कि संबंधित जांच अधिकारी के

पास मामले की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए जे.ए.सी. सल्दान्हा बनाम पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना और अन्य, (1979) आईएलआर (पटना) 459 में कार्यवाही रद्द कर दी।

अपील में, अपीलकर्ता-राज्य ने तर्क दिया कि निर्णय पर निर्भरता का कोई परिणाम नहीं था क्योंकि इसे बिहार राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। वी.जे.ए.सी. सलदान्हा और अन्य। आदि, [1980] एससीसी 554।

न्यायालय ने अपीलो को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया-

यह अजीब बात है कि जिस फैसले को इस न्यायालय ने लगभग चौथाई सदी पहले खारिज कर दिया था, उसे बार द्वारा उद्धृत किया गया था और अदालत ने इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और उक्त खारिज किए गए फैसले पर भरोसा करते हुए मामले का निपटारा कर दिया।

उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने वाली अदालत को एकल न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया। बार के सदस्य न्यायालय के अधिकारी होते हैं। न्यायालय की सहायता करना और उसे गुमराह न करना उनका परम कर्तव्य है। एक न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए जिसे उसी उच्च न्यायालय या इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने तथ्य का खुलासा किए बिना खारिज कर दिया है।

यह कि इसे खारिज कर दिया गया है, गंभीर चिंता का विषय है। यह एक बात है कि न्यायालय पहले के फैसले को पलटने वाले फैसले पर गौर करता है और उस पर विचाराधीन तथ्यों पर बाद के फैसले की प्रयोज्यता पर निर्णय लेता है। मामले को बहुत ही सहजता से निपटाया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के वकील का यह कर्तव्य था कि वह इसे प्रस्तुत करे व न्यायालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष जिस निर्णय पर भरोसा किया था, उसे इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील का यह कर्तव्य था कि वह खारिज किए गए फैसले का हवाला न दे। ऐसा नहीं है कि यह निर्णय पुरातनता में खो गया है। इसका प्रतिपादन होने के बाद से इसे बड़ी संख्या में मामलों में संदर्भित किया गया है। [506-सी-एफ; 506-जी-एच]

2. मामले को वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है ताकि वह याचिकाओं पर नए सिरे से विचार कर सके और निर्णय और अन्य सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सके। [507-बी-सी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 870-872/2004

सीआरएल में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.4.2003 से, जो कि 2003 के एम. नं. 306, 141 और 1491 में पारित किया गया।

अपीलकर्ता की ओर से राधा श्याम जेना।

प्रतिवादी की ओर से जन कल्याण दास।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ0 अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया

उड़ीसा राज्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 482 के तहत दायर तीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाता है।

याचिकाएँ दायर की गईं, अन्य बातों के साथ-साथ, -(1) आरोप को रद्द करने के लिए जांच अधिकारी (सतर्कता सेल) भुवनेश्वर द्वारा दायर शीट; (2) भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 468, 471 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने वाले दिनांक 9.12.2002 के आदेश को रद्द करना; और (3) संहिता की धारा 205 के संदर्भ में प्रार्थना को अस्वीकार करने के पारित आदेश को रद्द करने और गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी करने के निर्देश देने वाले आदेश को वापस लेने की प्रार्थना को खारिज करने के लिए। गौरतलब है कि विजिलेंस

जी.आर. 2001 का केस नंबर 17 प्रासंगिक समय पर विशेष सी.जे.एम. की अदालत में लंबित था।

(सतर्कता),भुवनेश्वर। मुकदमेबाजी का प्रारंभिक बिंदु 29.5.2001 को पुलिस निरीक्षक, सतर्कता सेल, यूनिट कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा पहली सूचना रिपोर्ट तैयार करना था। हालाँकि कई सरकारी अधिकारियों पर आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'पीसी एक्ट') के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अभियुक्तों के अनुसार जांच अधिकारी को आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और आरोप पत्र केवल वर्तमान आरोपी प्रतिवादी के संबंध में दायर किया गया था। चूंकि संज्ञान में गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाएं दायर की गईं। संहिता की धारा 482 के तहत एक अलग याचिका यह रुख अपनाते हुए दायर की गई थी कि संबंधित जांच अधिकारी के पास मामले की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उच्च न्यायालय ने अंतिम वर्णित याचिका को महत्वपूर्ण माना और अन्य को परिणामी माना।

आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने माना कि जांच अनधिकृत थी और इसलिए, कार्यवाही दूषित हो गई थी। जे.ए.सी. में पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा रखा गया था। सलादानहा बनाम

पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना और अन्य, (1979) आईएलआर पटना 459। तदनुसार, कार्यवाही रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट ने अन्य याचिकाओं पर अलग से विचार करना जरूरी नहीं समझा।

अपील के समर्थन में राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था। ऊपर संदर्भित पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने का वास्तव में कोई परिणाम नहीं था क्योंकि प्रश्नगत निर्णय को इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य और अन्य बनाम जे.ए.सी. मामले में रद्द कर दिया गया है। बिहार राज्य व अन्य बनाम सलदान्हा और अन्य। आदि, [1980] 1 एससीसी 554।

अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टें [2004] समर्थन। 3 एस.सी.आर. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय, जिस पर भरोसा किया गया था, इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है और दुर्भाग्य से इस न्यायालय के निर्णय के प्रभाव पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक साजिश और दुर्भावना का परिणाम था। यदि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो यह अजीब है कि अकेले प्रतिवादी को उठाया गया और उसके खिलाफ विभिन्न अपराध करने का आरोप लगाया गया। इसलिए, यह

प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

यह अजीब बात है कि एक निर्णय जिसे इस न्यायालय ने लगभग चौथाई शताब्दी पहले खारिज कर दिया था, बार द्वारा उद्धृत किया गया था और अदालत ने इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और उक्त खारिज किए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने वाले इस न्यायालय के फैसले को मामले से निपटने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभियुक्त के विद्वान वकील, जिनसे निर्णय जानने की अपेक्षा की जाती है, ने इस पहलू को विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया। बार के सदस्य न्यायालय के अधिकारी होते हैं। न्यायालय की सहायता करना और उसे गुमराह न करना उनका परम कर्तव्य है।

किसी न्यायालय के फैसले का हवाला देना, जिसे उसी उच्च न्यायालय या इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने खारिज कर दिया है, इस तथ्य का खुलासा किए बिना कि इसे खारिज कर दिया गया है, गंभीर चिंता का विषय है। यह एक बात है कि न्यायालय पहले के फैसले को पलटने वाले फैसले पर गौर करता है और उस पर विचाराधीन तथ्यों पर बाद के फैसले की प्रयोज्यता पर निर्णय लेता है। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता

कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख नहीं किया।

यह सब दर्शाता है कि मामले को बहुत ही लापरवाही से निपटाया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय से यह ज्ञात हुआ कि सुनवाई 13.3.2003 को समाप्त हुई और निर्णय 25.4.2003 को सुनाया गया। यह निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के वकील का कर्तव्य था कि वह न्यायालय के ध्यान में लाए कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष जिस निर्णय पर भरोसा किया था।

इस कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है. इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वकील का यह कर्तव्य था कि वह खारिज किए गए फैसले का हवाला न दें। ऐसा नहीं है कि यह निर्णय पुरातनता में खो गया है।

इसका प्रतिपादन होने के बाद से इसे बड़ी संख्या में मामलों में संदर्भित किया गया है। इसे हाल ही में कई मामलों में संदर्भित किया गया है जैसे एस.एम. दत्ता बनाम एच राज्य उड़ीसा राज्य बनाम नलिनीकांत मुदुली [पसायत, जे.]

गुजरात, [2001] 7 एससीसी 659, एम.सी. अब्राहम बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2003]

2 एससीसी 649, भारत संघ बनाम प्रकाश पी. हिंदुजा, [2003] 6 एससीसी 195 और इससे पहले हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, [1992] मामले में कई बार उद्धृत निर्णयों में .1 एससीसी 335, जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी, [1992] 4 एससीसी 305, भारत संघ बनाम डब्ल्यू.एन. चड्ढा, [1993] सप्लिमेंट। 4 एससीसी 260 एवं बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, [1992] पूरक। 1 एससीसी 222. हम केवल पेशेवर आचरण के गिरते मानकों पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाता है। हम मामले को वापस उच्च न्यायालय के पास भेजते हैं ताकि वह याचिकाओं पर नए सिरे से विचार कर सके और इस न्यायालय के फैसले और अन्य सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सके। उच्च न्यायालय के समक्ष सभी याचिकाएँ जिनका निपटारा आक्षेपित निर्णय द्वारा कर दिया गया था, उन्हें कानून के अनुसार निपटाए जाने के लिए उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा।

ऊपर बताई गई सीमा तक अपील की अनुमति है।

अपील स्वीकार की गई.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रीतू चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।